कंपनी निवेश : वर्ष 2006-07 में वृद्धि और वर्ष 2007-08 के लिए संभावनाएँ*

प्रस्तुत लेख में निजी कंपनी क्षेत्र के वर्ष 2006-07 में नियत पूँजी निवेश के विन्यास और स्तर पर चर्चा की गयी है, जो उन कंपनियों पर आधारित है, जिन्हें वर्ष 2006-07 के दौरान और उसके पिछले वर्षों में संस्थागत साहाय्य कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इस अध्ययन में पहली बार उन कंपनियों के पूँजीगत व्यय का मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया गया है, जिन्हें संस्थागत साहाय्य कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था । परिकल्पित कुल पूँजीगत व्यय वर्ष 2006-07 में सुस्पष्ट रूप से अधिक हुए, जो बढ़े हुए निवेश अवसरों को प्रतिबिंबित करते हैं। बुनियादी सुविधा वाली परियोजनाएँ, खासकर विद्युत परियोजनाएँ इस दृश्य पर हावी होती आयी हैं। वर्ष 2006-07 में स्वीकृत साहाय्य वाली परियोजनाओं की कुल लागत बढ़कर 2,83,440 करोड़ रुपये हो जाने का कारण यह था कि 88 बड़ी परियोजनाओं में से प्रत्येक की परियोजना लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक थी और कुल लागत 2,01,356 करोड़ रुपये या कुल परियोजना लागत का दो-तिहाई हिस्सा थी, जो वर्ष 2005-06 में 49 परियोजनाओं की 74,988 करोड़ रुपये लागत की तुलना में अधिक था । गुजरात 86 परियोजनाओं में 73,170 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ, जो कुल निवेश का 25.8 प्रतिशत हिस्सा होता था, पहले स्थान पर था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान आता है । पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन, पूँजीगत वस्तुओं के आयात और परिकल्पित क्षमता वृद्धि में अधिक तेजी, जिसका समर्थन उन्नत कंपनी लाभप्रदता, उच्च क्षमता उपयोग दरों और वर्ष 2006-07 की सभी तिमाहियों में विनिर्माण क्षेत्र में तगड़ी जीडीपी वृद्धि ने किया, स्थायी पूँजी निवेश की गति में निरंतरता की ओर इशारा करती हैं । कंपनी निवेश में बदलाव, जो वर्ष 2002-03 में आरंभ हुआ और वर्ष 2004-05 में सबसे अधिक परिलक्षित हुआ, वर्ष 2007-08 में भी बने रहने की उम्मीद की जाती है ।

* सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के कंपनी अध्ययन प्रभाग में तैयार किया गया ।

परिचय

नये संयंत्र और उपकरण में निवेश अनिवार्य होता है यदि कारोबार की उत्पादकता बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि बनाये रखने और इसके साथ-साथ प्रतियोगिता में जमे रहने के लिए नयी प्रौद्योगिकी के साथ कदम मिलाकर चलना हो । कारोबारी निवेश में वृद्धि से पूँजीगत स्टॉक में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है, जो दीर्घावधि के लिए आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक होती है । एक वर्ष पश्चात् कंपनी निवेश में होने वाली वृद्धि के बारे में जानने के लिए इस लेख में निजी और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों के पूँजीगत व्यय का मूल्यांकन किया गया है । इस विश्लेषण में सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के कार्यसंपादन के बारे में कारोबारी प्रत्याशाओं और विशेष रूप से आधारभूत संरचना और विनिर्माणक्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है ।#

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह अध्ययन इस प्रकार किया गया है कि कंपनी निवेश में संभावित वृद्धि को मुख्यतया उन आँकड़ों के आधार पर विश्लेषित किया जाये, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों और अन्य बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत साहाय्य वाली परियोजनाओं के क्रमबद्ध ब्यौरों से प्राप्त किया गया है । यह दृष्टिकोण डॉ.सी.रंगराजन द्वारा 'कंपनी क्षेत्र में पूँजीगत व्यय का पूर्वानुमान करना' शीर्षक से 'इकॉनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली' के दिसंबर 13, 1970 के अंक में प्रकाशित लेख में प्रतिपादित प्रणाली पर आधारित है । यह प्रणाली मुख्यतया इस धारणा पर आधारित थी कि निजी कंपनी प्रतिष्ठान, जो अधिक राशि के निवेश वाली परियोजनाओं पर काम करते हैं, सामान्यत:बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आंशिक वित्तपोषण का अनुरोध करते हैं । और इसीलिए इस विधि के अनुसार पूँजीगत व्यय में संभावित वृद्धि का मोटे तौर पर मूल्यांकन वार्षिक रूप से कुल पूँजीगत व्यय के चरणबद्ध ब्यौरों के आधार पर किया जा सकता है । इस विश्लेषण में निवेश के उस स्तर के बारे में संकेत किया गया है, जिससे आगे बढ़ना होगा, जबकि अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि आने वाले वर्ष में निवेश को पिछले वर्ष के स्तर से बढ़कर दिखाना है ।

तथापि, सरकारी नीतियों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप हाल के समय में कंपनियाँ उत्साहवर्द्धक पूँजी बाजारों का और समुद्रपार उपलब्ध न्यून लागत वाली निधियों का लाभ उठाते हुए घरेलू इक्विटी और विदेशी मुद्रा परिवर्तनशील बांडों (एफसीसीबी) सहित बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के माध्यम से काफी धनराशि जुटा रही हैं । पहली बार इस अध्ययन में यह प्रयास किया गया है कि इन कंपनियों के पूँजीगत व्यय के बारे में भी बताया जाये । निजी कंपनी क्षेत्र की कंपनियाँ भी ऋणों, बांडों/डिबेंचरों और एडीआर/जीडीआर के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन जुटा रही हैं । तथापि, आँकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण ऐसी कंपनियों के पूँजीगत व्यय के बारे में बताने का प्रयास नहीं किया गया है ।

क्षेत्र-विस्तार और व्याप्ति

इस अध्ययन में पूँजीगत निवेश में वृद्धि के बारे में किया गया अनुमान अधिकतर निजी क्षेत्र की उन कंपनियों की परियोजनाओं पर आधारित है, जिन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जीवन बीमा निगम, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक्जिम बैंक और प्रमुख सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों से साहाय्य मिला था । बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध परियोजना रिपोर्टों में उद्योग, प्रयोजन और परियोजना के स्थान के अलावा प्रस्तावित निवेश और इसके चरणबद्ध ब्यौरों के बारे में जानकारी दी गयी है ।

यह नोट करते हुए कि कुछ कंपनियाँ अपने बड़े पूँजीगत परिव्यय का वित्तपोषण करने के लिए इक्विटी

पूर्व अध्ययन 'कंपनी निवेश : वर्ष 2005-06 में वृद्धि और वर्ष 2006-07 के लिए संभावनाएँ' आरबीआइ बुलेटिन के अगस्त 2006 के अंक में प्रकाशित किया गया था ।

पूँजी या ईसीबी भी जुटा सकती हैं, ऐसी कंपनियों की निवेश योजनाओं को भी इस अध्ययन में मिलाया गया । इक्विटी पूँजी का निर्गम करने वाली कंपनियों के लिए परिकल्पित पूँजीगत व्यय के लिए और तदनुकूल चरणबद्ध ब्यौरों के लिए आँकड़ों को उनके द्वारा सेबी के पास प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र के आँकड़ों से चुना गया है । इसी प्रकार, उन कंपनियों के मामले में, जिन्होंने ईसीबी के माध्यम से निधियाँ जुटायी थीं, वैसी कंपनियों के आँकड़ों को मिलाया गया, जहाँ रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत किये गये फार्म 83 में इंगित प्रधान प्रयोजन था पूँजीगत व्यय । तदनुकूल आहरण अनुसूची को प्रस्तावित वार्षिक व्यय के संकेत के रूप में लिया जाता है । उस मामले में, जहाँ कंपनी ने संदर्भ अवधि के दौरान अपने पूँजीगत व्यय का आंशिक वित्तपोषण करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता के लिए अनुरोध किया और ईसीबी के लिए भी संविदा की या इक्विटी पूँजी जारी की, बहुविध गणना से बचने के लिए सावधानी बरती गयी है।

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, प्राइवेट प्लेसमेंट, डिबेंचर/बांडों के निर्गम के माध्यम से या एडीआर/जीडीआर के माध्यम से निधियाँ जुटाने वाली कंपनियों द्वारा परिकल्पित पूँजीगत व्यय का अभिनिश्चय नहीं किया जा सका, जिसका कारण था उनके अंतिम उपयोग के बारे में और वर्षों से व्यय-पैटर्न के बारे में अपर्याप्त जानकारी होना । संभावित कंपनी निवेश के मूल्यांकन की वैधता इस धारणा पर आधारित है कि कंपनियाँ प्रारंभिक प्रस्ताव में बताये गये व्यय पैटर्न का पालन करती हैं ।

वर्तमान अध्ययन में ऐसी 1054 कंपनियों[1] का वर्णन किया गया है, जिनके पास 2,83,440 करोड़ रुपये की कुल परिकल्पित लागत वाली परियोजनाएँ हैं । इन कंपनियों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2006-07 में सहायता स्वीकृत की गयी थी । इसके अतिरिक्त इस अवधि में पहली बार 472 वैसी कंपनियों के प्रस्तावित निवेश को शामिल किया गया, जिन्होंने वर्ष 2006-07 में कुल 58,086 करोड़ रुपये के ईसीबी (एफसीसीबी सहित) के लिए संविदा की थी और 79 वैसी कंपनियों के कुल 4,064 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को शामिल किया गया, जिन्होंने वर्ष 2006-07 के दौरान घरेलू इक्विटी पूँजी का निर्गम किया । कुल मिलाकर, वर्ष 2006-07 में इन 1605 कंपनियों से कुल निवेश प्रस्ताव 3,45,590 करोड़ रुपये के बराबर थे, जो वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2011-12 तक के लिए किये गये थे ।

[1] अधिकांशतः 10 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली परियोजनाएँ । बिल्ड, ऑपरेट, ओन और ट्रांसफर (बीओडीटी) पर आधारित परियोजनाएँ निजी कंपनी क्षेत्र के पूँजीगत व्यय का मूल्यांकन करने के लिए शामिल की गयीं ।

ए. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सहायता-प्राप्त कंपनियों का परिकल्पित पूँजीगत व्यय

सबसे पहले, जिन कंपनियों को वर्ष 2006-07 में वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी और जिन कंपनियों को वर्ष 2006-07 के पूर्व सहायता स्वीकृत की गयी थी तथा जिनका पूँजीगत व्यय बाद के वर्षों में सुव्यवस्थित किया गया था, उन पर विचार किया गया । इसके बाद वर्ष 2006-07 के लिए कंपनी निवेश का अनुमान लगाया गया, जिसके लिए अलग-अलग वर्षों में पूँजीगत व्ययों के समयानुसार आँकड़ों को उपयुक्त रूप से मिलाया गया। उन मामलों में, जहाँ किसी कंपनी ने एक से अधिक संस्था के पास परियोजना साहाय्य के लिए अनुरोध किया था, यह सावधानी बरती गयी कि उसे अध्ययन में एक ही बार शामिल किया जाये । पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के क्रमबद्ध रूप में संशोधनों को यथासंभव सीमा तक समाविष्ट करने के प्रयास किये गये। इस पद्धति से समेकित आँकड़ों को सारणी 1 में प्रस्तुत किया गया है । क्षैतिज रूप से पढ़ने पर यह उन पूँजीगत व्ययों को दर्शाता है, जो उन परियोजनाओं पर भिन्न-भिन्न वर्षों में किये जाते होंगे, जिनके लिए किसी दिये हुए वर्ष में परियोजनाओं को साहाय्य प्रदान किया गया था । उदग्र रूप से पढ़ने पर यह उस पूँजीगत व्यय को दर्शाता है, जो किसी वर्ष उन परियोजनाओं पर किया जाता, जिन्हें उस वर्ष और पिछले वर्षों में साहाय्य प्रदान किया गया था।

सारणी 1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2005-06 तक स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2006-07 के दौरान 59,232 करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय किये जाने की उम्मीद की गयी थी । वर्ष 2006-07 के दौरान नयी स्वीकृतियों में और 95,806 करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय वर्ष 2006-07 में (कॉलम 12, सारणी 1) करने की परिकल्पना की गयी थी। इस प्रकार, कुल पूँजीगत व्यय, जो वर्ष 2006-07 के दौरान किया जाता उसकी राशि 1,55,038 करोड़ रुपये के बराबर थी। वर्ष 2006-07 में न केवल परियोजनाओं की संख्या बढ़ी, वरन् उच्च लागत वाली परियोजनाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी ।

इसके परिणामस्वरूप, निजी कंपनी क्षेत्र द्वारा योजनाबद्ध पूँजीगत व्यय में वर्ष 2005-06 के दौरान 23.1 प्रतिशत वृद्धि के अतिरिक्त वर्ष 2006-07 में 60.2 तक वृद्धि होने की संभावना है । कुछ कंपनियों के बारे में, जिन्हें वर्ष 2006-07 में साहाय्य स्वीकृत किया गया था, यह पाया गया कि उन्होंने वर्ष 2005-06 में ही 14,903 करोड़ रुपये खर्च कर दिये थे । इस पर विचार करते हुए कुल पूँजीगत व्यय, जो वर्ष 2005-06 के दौरान किया गया होता, उसकी राशि 96,766 करोड़ रुपये के बराबर होती है ।

ए1. वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ

संस्थागत साहाय्य में शामिल 1054 कंपनियों के पास कुल 2,83,440 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएँ थीं । इसमें वर्ष 2004-05 से 2011-12 की अवधि के दौरान आठ वर्षों तक खर्च करने की जो परिकल्पना की गयी थी, वह वर्ष 2005-06 में संस्थागत साहाय्य में शामिल 812

सारणी 1 : वाणिज्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिन परियोजनाओं के लिए सहायता स्वीकृत की गई, उनके पूंजीगत व्यय को चरणबद्ध करना

(करोड़ रुपए)

वर्ष के दौरान पूंजी व्यय → स्वीकृति का वर्ष ↓	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च 1996 तक	42,613	22,426	7,599	3,156	1,988	1,773	1,005	599				
1996-97	21,917	20,044	8,592	2,800	588	618	617	594	463	176	136	
1997-98	4,437	21,359	19,122	10,111	3,833	1,148	889	703	566	195	101	
1998-99	1,408	6,415	23,321	18,622	10,248	3,340	1,545	1,701	725	184	99	
1999-2000	13	256	8,286	11,971	11,640	7,107	5,603	695	468			
2000-01	22	32	36	4,085	17,054	14,145	10,367	3,830	1,335	717		
2001-02			62	266	6,604	8,384	6,386	1,990	1,318	115	24	
2002-03			5	30	96	680	5,763	5,429	1,708	574	573	
2003-04				1,313	517	547	8,285	26,309	23,286	5,429	2,586	300
2004-05								5,815	36,709	33,193	11,810	5,143
2005-06									9,858	41,280	43,903	23,707
2006-07									2,172	14,903	95,806	96,098
2006-07 तक का योग	70,411	70,532	67,023	52,355	52,568	37,742	40,459	47,665	78,608	96,766	1,55,038	1,25,248
कुल योग # $	**70,691**	**70,724**	**67,131**	**52,435**	**52,668**	**37,742**	**40,459**	**47,665**	**78,608**	**96,766**	**1,55,038**	**1,25,248**
प्रतिशत परिवर्तन	**9.9**	**0.0**	**–5.1**	**–21.9**	**0.4**	**–28.3**	**7.2**	**17.8**	**64.9**	**23.1**	**60.2**	

: इसमें बिल पुनर्भुनाई योजना और तकनीकी विकास निधि योजना के अंतर्गत आइ डी बी आइ द्वारा प्रदत्त सहायता शामिल है।

$: कंपनी निवेश के अनुमान प्रत्याशित हैं और ये नेशनल एकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स में दिए गए पूर्व निर्धारित निवेश से व्याप्ति और पद्धति में प्रत्याशित अनुमानों से भिन्न हैं। कृपया विवरण हेतु रिज़र्व बैंक आफ इंडिया आकेज़नल पेपर्स के 1999 के मानसून अंक में प्रकाशित लेख ''ग्रोथ ऑफ कार्पोरेट इनवेस्टमेंट : ऐन अटेम्प्ट एट प्रोजेक्शन फार 1999-2000" के साथ संलग्न तकनीकी नोट भी देखें।

सारणी 2 : 2005-06 और 2006-07 में स्वीकृत परियोजनाओं का चरणबद्ध पूंजी व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष के दौरान पूंजी व्यय → परियोजनाओं का पूंजी व्यय ↓	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	परियोजनाओं की संख्या 812								
स्वीकृति का वर्ष : 2005-06	9,858	41,280	43,903	23,707	8,501	2,263	1,787	–	1,31,299
	(7.5)	(31.4)	(33.4)	(18.1)	(6.5)	(1.7)	(1.4)	–	(100.0)
	परियोजनाओं की संख्या 1054								
स्वीकृति का वर्ष : 2006-07	2,172	14,903	95,806	96,098	51,693	15,111	4,887	2,770	2,83,440
	(0.8)	(5.3)	(33.8)	(33.9)	(18.2)	(5.3)	(1.7)	(1.0)	(100.0)

– : शून्य / नगण्य।

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

कंपनियों के 1,31,299 करोड़ रुपये के परिकल्पित खर्च के दुगुने से भी अधिक था (सारणी 2) । वर्ष 2006-07 में नयी स्वीकृतियों के चरणबद्ध ब्यौरे दर्शाते हैं कि कुल प्रस्तावित खर्च का 33.8 प्रतिशत हिस्सा, जो 95,806 करोड़ रुपये राशि के बराबर होता है, वर्ष 2006-07 में खर्च किया जाना है ंऔर लगभग इसके बराबर राशि (96,098 करोड़ रुपये), जो अन्य 33.9 प्रतिशत का द्योतक है, अगले वर्ष, अर्थात् वर्ष 2007-08 में खर्च की जानी है । इन कंपनियों द्वारा कुल परियोजना लागत का लगभग 5.3 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2005-06 में पहले ही खर्च किया जा चुका है ।

ए2. परियोजनाओं का उद्योगवार पैटर्न

सारणी 3 में औद्योगिक कार्यकलाप के आधार पर वर्ष 2006-07 में स्वीकृत साहाय्य वाली परियोजनाओं के उद्योगवार वितरण को प्रस्तुत किया गया है, जैसाकि परियोजना रिपोर्टों में इंगित किया गया है । यह नोट किया जाये कि यह वर्गीकरण कुछ उभरती कोटियों, यथा, आइटी पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), आदि का भी द्योतक है ।

आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भारी निवेश का प्रदर्शन करते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुप, जिसमें वर्ष 2006-07 में 37

चार्ट 1 : समस्त परियोजना लागत में प्रमुख उद्योगों का हिस्सा

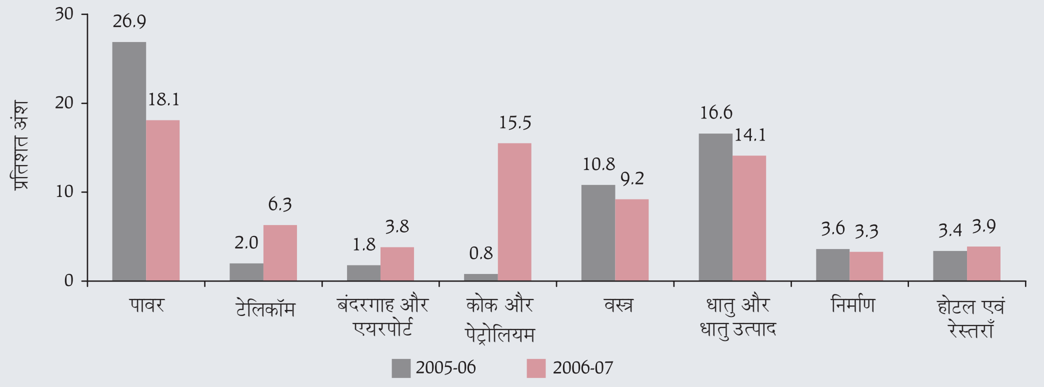

आइटी पार्क और एसईजेड परियोजनाएँ शामिल थीं, का हिस्सा कुल परियोजना खर्च के 35.9 प्रतिशत का था, जिसकी राशि 1,01,744 करोड़ रुपये थी । इस विशाल प्रस्तावित निवेश का आधा भाग विद्युत परियोजनाओं (51,451 करोड़ रुपये) में लगाया गया था, जिसके बाद 9 टेलिकॉम परियोजनाएँ (17,950 करोड़ रुपये), 8 सड़क, भंडारण और जल प्रबंधन परियोजनाएँ (13,083 करोड़ रुपये) और 7 बंदरगाहों और एयरपोर्ट परियोजनाओं (10,745 करोड़ रुपये) का स्थान है । एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आइटी पार्क परियोजनाओं में 8,515 करोड़ रुपये का निवेश परिकल्पित था ।

कोक और पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित परियोजनाओं में 44,083 करोड़ रुपये (सभी परियोजनाओं की लागत का 15.5 प्रतिशत) के पूँजीगत परिव्यय की परिकल्पना 11 परियोजनाओं में की गयी थी । इसके बाद धातु और धातु उत्पाद और कपड़ा उद्योग से संबंधित परियोजनाओं का स्थान है, जिनका हिस्सा क्रमशः 14.1 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत था । वर्ष 2006-07 में स्वीकृत साहाय्य वाली परियोजनाओं की अधिकतम संख्या 258 पर कपड़ा उद्योग की थी (वर्ष 2005-06 में 158 परियोजनाओं के अतिरिक्त), जिसके बाद धातु और धातु उत्पाद से संबंधित 130 परियोजनाओं का स्थान है । सेवा-उद्योगों के बीच होटल उद्योग का हिस्सा 3.9 प्रतिशत और उसके बाद निर्माण उद्योग का हिस्सा 3.3 प्रतिशत था (चार्ट 1) ।

ए3. परियोजनाओं का आकारवार पैटर्न

सारणी 4 में वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत साहाय्य वाली परियोजनाओं का आकारवार चित्र प्रस्तुत किया गया

सारणी 3 : परियोजनाओं का उद्योगवार वितरण तथा 2005-06 औप 2006-07 में उनकी लागत

उद्योग	2005-06			2006-07		
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत राशि (करोड़ रुपए)	परियोजना लागत प्रतिशत अंश	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत राशि (करोड़ रुपए)	परियोजना लागत प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7
1. इंफ्रास्ट्रक्चर	109	44,541	33.9	125	1,01,744	35.9
i) बिजली	66	35,358	26.9	64	51,451	18.2
ii) दूरसंचार	5	2,639	2.0	9	17,950	6.3
iii) बंदरगाह और एयरपोर्ट	3	2,295	1.8	7	10,745	3.8
iv) सड़क भंडारण और जल प्रबंधन	22	2,386	1.8	8	13,083	4.6
v) एसईजेड, औद्योगिक बॉयोटेक और आइटी पार्क	13	1,864	1.4	37	8,515	3.0
2. चीनी	20	2,857	2.2	33	8,867	3.1
3. वस्त्र	158	14,128	10.8	258	25,933	9.2
4. कागज और कागज केउत्पाद	23	2,397	1.8	24	2,915	1.0
5. कोक और पेट्रोलियम उत्पाद	2	1,107	0.8	11	44,083	15.5
6. रसायन और पेट्रोरसायन	26	3,021	2.3	35	4,136	1.5
7. सीमेंट	13	1,945	1.5	27	10,567	3.7
8. धातु और धात्विक उत्पाद	126	21,799	16.6	130	39,876	14.1
9. इलेक्ट्रिकल और इलैक्ट्रिकल से इतर	22	384	0.3	20	4,486	1.6
10. परिवहन उपस्कर	13	988	0.8	29	5,174	1.8
11. निर्माण	33	4,700	3.6	34	9,277	3.3
12. होटल और भोजनालय	37	4,454	3.4	74	11,122	3.9
13. परिवहन सेवाएं	21	16,947	12.9	17	1,561	0.5
14. मनोरंजन	9	1,807	1.4	20	761	0.3
15. सूचना प्रौद्योगिकी	7	2,683	2.0	8	228	0.1
16. अन्य*	193	7,540	5.7	209	12,710	4.5
कुल	**812**	**1,31,299**	**100.0**	**1054**	**2,83,440**	**100.0**

* : इसमें वे उद्योग शामिल हैं जिनका 2004-05 और 2005-06 की परियोजनाओं की कुल लागत में प्रत्येक का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है।

सारणी 4 : 2005-06 और 2006-07 में परियोजनाओं का आकारवार वितरण और उनकी लागत

परियोजनाओं का आकार (करोड़ रुपए)	2005-06			2006-07		
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	
		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत अंश		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7
10 से कम	172	713	0.5	48	285	0.1
10 से 50	306	7,834	6.0	475	12,064	4.3
50 से 100	118	8,523	6.5	191	13,790	4.9
100 से 200	84	12,252	9.3	131	18,808	6.6
200 से 500	83	26,989	20.6	121	37,137	13.1
500 और उससे अधिक	49	74,988	57.1	88	2,01,356	71.0
योग	**812**	**1,31,299**	**100.0**	**1054**	**2,83,440**	**100.0**

है । वर्ष 2006-07 में परियोजनाओं की कुल लागत में तेज वृद्धि बहुत हद तक उन 88 बड़ी परियोजनाओं के कारण हुई, जिनमें से प्रत्येक की परियोजना लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक थी । इन परियोजनाओं की कुल राशि 2,01,356 करोड़ रुपये थी, जो कुल परियोजना लागत के दो-तिहाई भाग से अधिक के लिए जिम्मेवार थी, जबकि वर्ष 2005-06 में 49 परियोजनाओं की कुल राशि 74,988 करोड़ रुपये थी ।

ए4. परियोजनाओं का राज्यवार पैटर्न

सारणी 5 में वर्ष 2006-07 में स्वीकृत परियोजनाओं द्वारा प्रकट किये गये प्रस्तावित निवेश का राज्यवार पैटर्न प्रस्तुत किया गया है । इस पैटर्न में प्रतिवर्ष फेर-बदल होता है, क्योंकि कुछ बड़ी परियोजनाओं के स्थान काफी हद तक पैटर्न को बदल देते हैं । ऐसी परियोजनाओं के साथ, जिनका कुल निवेश आशय 73,170 करोड़ रुपये की राशि के बराबर है, गुजरात 86 परियोजनाओं के साथ महाराष्ट्र को स्थानच्युत करते हुए पहले स्थान पर पहुँच गया । यह सभी 1054 परियोजनाओं के कुल निवेश आशय का 25.8 प्रतिशत होता था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (8.9 प्रतिशत), महाराष्ट्र (8.6 प्रतिशत), तमिलनाडु (8.6 प्रतिशत) की परियोजनाओं का स्थान आता है, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 25,000 करोड़ रुपये कर निवेश हुआ है (चार्ट 2) । एक से अधिक राज्यों में अवस्थित 46 परियोजनाओं में निवेश की राशि 25,428 करोड़ रुपये के बराबर थी (मल्टी स्टेट परियोजनाओं की कोटि में

चार्ट 2 : समस्त परियोजना लागत में प्रमुख राज्यों का हिस्सा

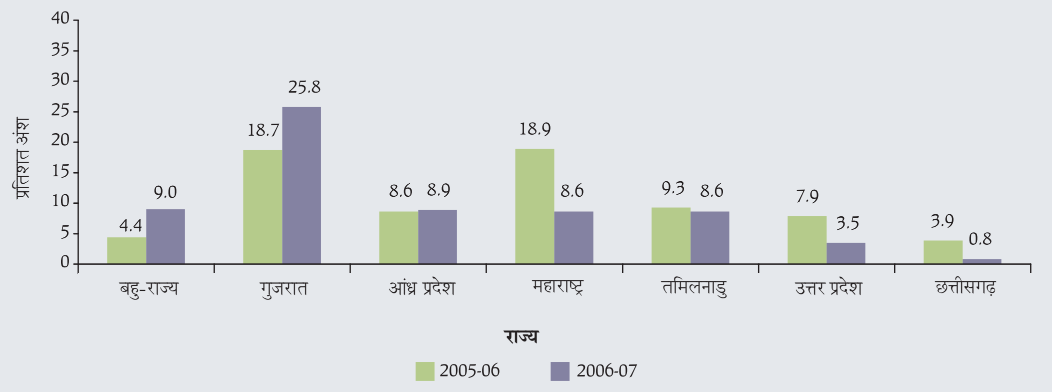

सारणी 5 : 2005-06 और 2006-07 में परियोजनाओं का राज्यवार वितरण और उनकी लागत						
राज्य	2005-06			2006-07		
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	
		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत अंश		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	76	11,254	8.6	105	25,173	8.9
छत्तीसगढ़	19	5,162	3.9	13	2,365	0.8
दिल्ली	24	2,127	1.6	19	6,359	2.2
गुजरात	95	24,531	18.7	86	73,170	25.8
हरियाणा	29	1,805	1.4	42	3,897	1.4
हिमाचल प्रदेश	19	9,325	7.1	30	2,644	0.9
झारखंड	8	367	0.3	13	7,174	2.5
कर्नाटक	51	4,537	3.5	91	19,930	7.0
मध्य प्रदेश	12	2,514	1.9	23	4,878	1.7
महाराष्ट्र	121	24,828	18.9	142	24,330	8.6
उड़ीसा	20	4,525	3.5	23	14,806	5.2
पंजाब	27	2,041	1.5	48	5,902	2.1
राजस्थान	27	2,466	1.9	38	9,806	3.5
सिक्कीम	–	–	–	3	9,418	3.3
तमिलनाडु	124	12,160	9.3	157	24,299	8.6
उत्तर प्रदेश	50	10,415	7.9	60	9,836	3.5
उत्तराखंड	24	2,959	2.2	31	5,633	2.0
पश्चिम बंगाल	27	2,548	1.9	37	3,404	1.2
बहु - राज्य	29	5,730	4.4	46	25,428	9.0
अन्य*	30	2,005	1.5	47	4,988	1.8
योग	**812**	**1,31,299**	**100.0**	**1054**	**2,83,440**	**100.0**

– : शून्य

* इसमें राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में से प्रत्येक का हिस्सा 2005-06 और 2006-07 में परियोजनाओं की सकल लागत में 1 प्रतिशत से कम है।

प्रस्तुत) । नयी स्वीकृत परियोजनाओं के संदर्भ में तमिलनाडु 157 परियोजनाओं के साथ पहले स्थान पर था, जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान 142 परियोजनाओं के साथ और आंध्र प्रदेश का स्थान 105 परियोजनाओं के साथ आता है ।

ए5. परियोजनाओं का प्रयोजनवार पैटर्न

वर्ष 2006-07 के दौरान नयी परियोजनाओं की संख्या 566 थी, जबकि वर्ष 2005-06 में नयी परियोजनाओं की संख्या 393 थी (सारणी 6) । ये परियोजनाएँ 1,88,534

सारणी 6 : 2005-06 और 2006-07 में परियोजनाओं का प्रयोजनवार वितरण और उनकी लागत						
प्रयोजन	2005-06			2006-07		
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	
		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत अंश		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7
नया	393	76,659	58.4	566	1,88,534	66.5
विस्तार और आधुनिकीकरण	379	49,525	37.7	415	77,956	27.5
विशाखीकरण	6	627	0.5	32	6,481	2.3
अन्य	34	4,488	3.4	41	10,469	3.7
जोड़	**812**	**1,31,299**	**100.0**	**1054**	**2,83,440**	**100.0**

करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के 66.5 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार थीं, जबकि वर्ष 2005-06 में कुल परियोजना लागत 76,659 करोड़ रुपये थी; और इसमें 33 बड़ी परियोजनाएँ शामिल थीं, जिनकी परियोजना लागत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक थी । अन्य 415 परियोजनाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण वर्ष 2006-07 में प्रस्तावित था और वे कुल परियोजना लागत के 27.5 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार थीं, जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान 379 परियोजनाओं का हिस्सा 37.7 प्रतिशत था ।

बी. ईसीबी से निधियाँ जुटाने वाली कंपनियों के परिकल्पित पूँजी व्यय

यह उल्लेखनीय है कि ईसीबी (एफसीसीबी सहित) निधीयन ने पिछले तीन वर्षों में बड़ी भूमिका धारण कर ली है, जो संभवतः पालिसी अभिमुखता के परिणामस्वरूप है। रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत फार्म 83 में ईसीबी के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर संविदा-तय ऋण की राशि और इसकी आहरण अनुसूची मोटे तौर पर क्रमशः कंपनी के परिकल्पित पूँजी व्यय का और तदनुकूल चरणबद्ध अनुसूची का द्योतक होती है । किसी संदर्भ वर्ष में तब योजनाबद्ध पूँजीगत व्यय संदर्भ वर्ष तक और उसे शामिल करते हुए वर्षों में संविदा-तय ऋणों से प्रत्येक वर्ष आहरित ऋण की राशि के कुल जोड़ से प्राप्त किया जाता है । ऐसे मामलों में, जहाँ निजी कंपनी क्षेत्र की किसी कंपनी ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता के लिए अनुरोध किया था और संदर्भ वर्ष के दौरान अपने पूँजीगत व्यय का आंशिक वित्तपोषण करने के लिए ईसीबी के लिए भी संविदा की थी, वहाँ इस बात की सावधानी बरती गयी है कि दुबारा गणना से बचा जाये।

जिन कंपनियों ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध किया था, उन्हें छोड़कर ईसीबी के लिए संविदा करने वाली शेष कंपनियों की निवेश योजना वर्ष 2006-07 में 58,086 करोड़ रुपये की राशि के बराबर थी, जबकि वर्ष 2005-06 में यह 30,235 करोड़ रुपये के आसपास थी, वर्ष 2004-05 में 24,646 करोड़ रुपये और वर्ष 2003-04 में केवल 5,197 करोड़ रुपये थी । वर्ष 2006-07 के दौरान खर्च की जाने वाली अनुमानित पूँजीगत व्यय की राशि, जो वर्ष 2003-04 से ईसीबी के लिए संविदा करने वाली कंपनियों से आती, लगभग 49,084 करोड़ रुपये के बराबर होती है, जिसमें से 38,078 करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा उन ऋणों में से प्राप्त हुआ था, जिनके लिए वर्ष 2006-07 में ही संविदा की गयी थी ।

सी. आईपीओ/एफपीओ/राइट्स निर्गमों से निधियाँ जुटाने वाली कंपनियों के परिकल्पित पूँजीगत व्यय

वर्ष 2006-07 के दौरान निजी कंपनी क्षेत्र की 110 गैर-वित्तीय कंपनियाँ पब्लिक/राइट्स निर्गम लेकर आयीं, जिनकी कुल राशि 29,857 करोड़ रुपये के बराबर थी । सेबी के पास प्रस्तुत कंपनियों के विवरण-पत्र में दी गयी जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि इस राशि का तीन चौथाई भाग स्थायी निवेश पर खर्च किया जाना परिकल्पित था ।

तथापि, इन कंपनियों की कुल निवेश योजना 45,517 करोड़ रुपये की बड़ी राशि की थी, जिसका फैलाव वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2009-10 तक था । इस कुल राशि में से 17,010 करोड़ रुपये के पूँजी व्यय की राशि वर्ष 2006-07 के दौरान परिकल्पित थी। पहले की ही तरह उन कंपनियों के पूँजीगत व्यय को छोड़कर, जिन्होंने आंशिक वित्तपोषण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से साहाय्य का अनुरोध किया था या ईसीबी के लिए संविदा की थी, वर्ष 2006-07 के दौरान इक्विटी निर्गम द्वारा संसाधन जुटाने वाली शेष कंपनियों द्वारा परिकल्पित कुल निवेश योजना 4,064 करोड़ रुपये के बराबर थी । इनमें से लगभग 2,338 करोड़ रुपये और 1,161 करोड़ रुपये का व्यय वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान परिकल्पित था ।

मूल्यांकन और संभावनाएँ

वर्ष 2006-07 का मूल्यांकन

पिछले वर्ष से अर्थव्यवस्था का कार्यसंपादन अच्छा रहा है। लगातार चार वर्षों से आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से ऊपर रही है। पिछले तीन वर्षों से स्थायी निवेश में देखी गयी वार्षिक वृद्धि पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण विस्तार को प्रदर्शित करती है, जिसके चलते यह निजी क्षेत्र के स्थायी निवेश के साथ सबसे बड़ा चक्र बनाते हुए आशावादी कारोबारी विश्वास, उत्साहवर्द्धक लाभ और बढ़ते क्षमता उपयोग की प्रतिक्रिया में दृढ़ बनी रहती है। निवेश की अनुकूल स्थिति 11.5 प्रतिशत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में प्रचुरता से प्रतिबिंबित हुई, जो विनिर्माण क्षेत्र के 12.5 प्रतिशत के तगड़े कार्य संपादन से उत्साहित थी। वर्ष 2006-07 में पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में 18.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि ने पूँजीगत वस्तुओं के आयात में अप्रैल-जनवरी 2006-07 के दौरान 32.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था में निवेश कार्यकलाप के संबंध में तगड़ा समर्थक साक्ष्य प्रस्तुत किया है। सुदृढ़ औद्योगिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए बैंकों से उद्योग को दिये गये ऋण में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2006-07 में दर्ज की गयी और वह मुख्यतः आधारभूत संरचना, कपड़ा, लोहा और इस्पात और निर्माण उद्योगों की ओर निदेशित थी। वर्ष के दौरान बढ़ती ब्याज दर ने यद्यपि उपभोक्ता-व्यय में वृद्धि को कम किया, फिर भी इसने अभी भी निवेश संबंधी खर्च की गति को कम नहीं किया है, जो वर्ष के दौरान परिकल्पित निवेश में वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है।

परिकल्पित पूँजीगत व्यय में वृद्धि, जो वर्ष 2002-03 से स्थिर गति से ऊर्ध्वमुखी हो रही थी और वर्ष 2004-05 में सर्वाधिक हो गयी थी, वह कम होकर वर्ष 2005-06 में 23.1 प्रतिशत हो गयी। तथापि, वर्ष 2006-07 में स्वीकृत साहाय्य प्राप्त सभी परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत वर्ष 2005-06 के 1,31,299 करोड़ रुपये की तुलना में दुगुनी से भी अधिक होकर 2,83,440 करोड़ रुपये हो गयी। निरंतर सुधरा हुआ निवेश रुझान और कारोबारी विश्वास अधिक संख्या में फर्मों द्वारा किये गये पूँजीगत व्यय और ऐसे व्यय की सीमा में प्रतिबिंबित हुआ। वर्ष 2006-07 में परिकल्पित पूँजीगत व्यय, जिसमें पूर्व के सभी वर्षों में स्वीकृत साहाय्य वाली परियोजनाओं के लिए किया गया व्यय शामिल है, 1,55,038 करोड़ रुपये की राशि के बराबर है, जो पिछले वर्ष के व्यय से 60.2 प्रतिशत अधिक है। निवेश-आशय में तीव्र वृद्धि पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण उच्च आधार के बावजूद हुई।

बहुविध गणना से बचते हुए और उन कंपनियों के बारे में विचार करते हुए, जिन्होंने ईसीबी और घरेलू इक्विटी निर्गमों के माध्यम से संसाधनों का संग्रहण किया है, ऐसी कंपनियों द्वारा परिकल्पित व्यय की राशि क्रमशः 49,084 करोड़ रुपये और 2,338 करोड़ रुपये के बराबर थी। इस अध्ययन में शामिल कंपनियों के सभी स्रोतों से पूँजीगत व्यय आशयों को जोड़कर प्रस्तावित निवेश की राशि वर्ष 2006-07 में 2,06,460 करोड़ रुपये के बराबर होगी।

वर्ष 2007-08 के लिए संभावनाएँ

आर्थिक कार्यकलाप में वर्ष 2006-07 में काफी गति दिखाई पड़ी। आगे बढ़ते हुए, सकल माँग, जो निवेश के लिए मुख्य प्रेरक बल होती है, स्वस्थ गति से बढ़ने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमान है कि वास्तविक जीडीपी वर्ष 2007-08 में 8.5 प्रतिशत तक बढ़ेगी। तेजी से बढ़ती माँग की प्रत्याशा ने निजी कंपनी क्षेत्र को इष्टतम क्षमता-स्तर तक अपना परिचालन करने के लिए प्रेरित किया है। यह भी कि, सुदृढ़ एवं ठोस तुलनपत्रों की पृष्ठभूमि में कंपनी लाभप्रदता में निश्चित सुधार निवेश करने की उनकी क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। दूसरे शब्दों में , अधिक क्षमता में कटौती के साथ निवेश करने की उनकी योग्यता कारोबारी कंपनी क्षेत्र को निवेश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। औद्योगिक उत्पादन

में निरंतर गति के साथ निर्यात वृद्धि में निरंतर उछाल, जैसाकि इस वर्ष के पहले दो महीनों में देखने को मिला है, प्रेरणास्पद निवेश माँग में सहायक रहा है । बजट में किये गये उपाय, जिनमें आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है, संभवतः निवेश वातावरण को अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहन देंगे । हालाँकि, वर्ष 2007-08 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में माँग-वृद्धि में तेजी की प्रतिक्रिया में अपनी हाल की सुदृढ़ता को बनाये रख सकती है, इसमें कुछ नरमी इसके चक्रीय स्वरूप के कारण आ सकती है । कम जोखिम देश और विदेश में बढ़ती ब्याज दरों, संभावित करेंसी मूल्यवृद्धि और अनेक उद्योगों में मजदूरी खर्च के दबावों से उत्पन्न होती है । तथापि, ये कम जोखिमें सीमित रहती हैं और इनका समंजन उच्च वृद्धि की गति से और आसान वैश्विक चलनिधि के बीच निरंतर बड़े पूँजी अंतर्वाह की संभावना से हो सकता है ।

वर्ष 2007-08 के लिए निवेश, जिसकी योजना उन परियोजनाओं के आधार पर बनायी गयी थी, जिन्हें वर्ष 2006-07 तक के वर्षों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय साहाय्य स्वीकृत किया गया था, की कुल राशि 1,25,248 करोड़ रुपये के बराबर थी । वर्ष 2007-08 में प्रस्तावित निवेश की कुल राशि 1,48,207 करोड़ रुपये के बराबर होगी, यदि ईसीबी और इक्विटी निर्गमों के माध्यम से निधियाँ जुटाने वाली कंपनियों के 21,798 करोड़ रुपये और 1,161 करोड़ रुपये के पूँजीगत व्यय को इसमें जोड़ दिया जाये । तथापि, वर्ष 2007-08 में सकल पूँजीगत व्यय की गणना करने के लिए हमें इसमें वर्ष 2007-08 में किये जाने वाले पूँजीगत व्यय को जोड़ना होगा । इसलिए यदि वर्ष 2007-08 में सकल पूँजीगत व्यय को वर्ष 2006-07 में प्राप्त किये गये स्तर से पार कर जाना हो (अर्थात् बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास अनुरोध करने वाली या घरेलू इक्विटी पूँजी जारी करने वाली या ईसीबी के लिए संविदा करने वाली कंपनियों द्वारा सामूहिक रूप से परिकल्पित 2,06,460 करोड़ रुपये), तो वर्ष 2007-08 में पूँजीगत व्यय 58,253 करोड़ रुपये से ऊपर होना चाहिए। चूँकि कारोबार की स्थिति सामान्यतः स्वस्थ कंपनी तुलनपत्र के साथ समुन्नत लाभप्रदता और न्यून अप्रयुक्त क्षमता की पृष्ठभूमि में कंपनी निवेश माँग का समर्थन करने में सहायक है, इसलिए वर्ष 2007-08 में ऐसी किसी राशि का निवेश संभव लगता है । दूसरे शब्दों में, वर्ष 2007-08 कंपनी निवेश में वृद्धि का साक्षी होगा, जब 2006-07 की स्थिति से उसकी तुलना की जाये, अलबत्ता, उसकी गति धीमी रहेगी ।